भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *537

(दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए)

मेगा मूवी प्रोडक्शन स्टूडियो के लिए प्रस्ताव

***537. डॉ. थोल तिरूमावलवनः**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का एक मेगा मूवी प्रोडक्शन स्टूडियो शुरू करने और उससे रोजगार सृजन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके माध्यम से सृजित होने वाले रोजगार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव के तहत ऐसे मेगा मूवी प्रोडक्शन स्टूडियो में सरकारी निवेश किए जाने की संभावना है या यह निजी क्षेत्र या सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत होगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 01.04.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *537 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): सरकार फिल्मी सामग्री के विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी) स्कीम के माध्यम से फिल्म प्रोडक्शन इकोसिस्टम में सक्रिय रूप से सहायता करती है।

डीसीडीएफसी स्कीम केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसमें सरकार सिनेमाई उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष रुप से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

डीसीडीएफसी स्कीम के अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से सिनेमा के निर्माण को भी सुगम बनाती है। इससे क्षेत्रीय सिनेमा के साथ-साथ वृत्तचित्र भी शामिल हैं। इससे देश भर में स्थानीय तकनीशियनों, कलाकारों और सेवा प्रदाताओं के लिए रोजगार का सृजन होता है।

सरकार ने मुंबई में वर्ल्ड आडियो-विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स 2025) का आयोजन किया। यह "क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड" पहल के तहत भारत को सामग्री निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के सरकार की परिकल्पना के अनुरूप था। इस शिखर सम्मेलन ने भारतीय निर्माताओं, उत्पादकों और स्टार्टअप्स को 100 से अधिक देशों के वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, ओटीटी प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकी नेताओं के साथ जुड़ने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, सरकार ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण करारों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू सहयोग को भी प्रोत्साहित करती है। चूंकि इन परियोजनाओं में सरकारी सहयोग के साथ निजी निर्माताओं की भागीदारी होती है, इसलिए ये सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के अनुरूप संचालित होती हैं, जिनका उद्देश्य भारतीय ऑडियो-विजुअल क्षेत्र में निवेश और उन्नत फिल्म निर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है।

घरेलू फिल्म समारोहों के आयोजन हेतु सहायता के रूप में, राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित फिल्म समारोहों को अनुदान प्रदान किया जाता है। ऐसे समारोहों को चयनित फिल्म पैकेज उपलब्ध कराने, मास्टरक्लास एवं कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से भी सहायता प्रदान किया जाता है। एनएफडीसी संपूर्ण फिल्म इकोसिस्टम में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करते हुए विभिन्न राज्य फिल्म विकास निगमों के साथ सहयोग भी करता है। राज्य सरकारों की स्थानीय

फिल्म सामग्री के संरक्षण हेतु भी एनएफडीसी द्वारा सहयोग दिया जाता है। कई राज्य अपनी औद्योगिक विकास नीतियों के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल सहित फिल्म निर्माण स्टूडियो के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।

*****